समक्ष

रामेश्वर सिंह मलिक न्यायाधीश

चंदर भान सिंघल—याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य-प्रतिवादी

1995 का सीडब्ल्यूपी नंबर 4275

11 फ़रवरी 2015

भारत का संविधान, 1950 - अनुच्छेद 226 - सेवा की समाप्ति- विभागीय जांच - याचिकाकर्ता प्रोफ़ेसर- बीमार पड़ गए और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ चिकित्सा अवकाश के लिए आवेदन भेजा - जब उन्होंने ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया, तो

उन्हें शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई - कॉलेज के प्रबंधन ने जानबूझकर लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के आधार पर बर्खास्तगी का आदेश पारित किया - कोई विभागीय जांच नहीं की गई - राज्य ने प्रस्तुत किया कि चूंकि परिवीक्षा अवधि के दौरान समाप्ति आदेश पारित किया गया था, इसलिए कोई नियमित विभागीय जांच नहीं की जानी थी - माना गया कि चूंकि याचिकाकर्ता नियमित आधार पर सेवा कर रहा था, इसलिए कॉलेज प्रबंधन के पास बिना आचरण समाप्ति आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। समाप्ति आदेश के रूप में एक नियमित विभागीय जांच कलंकपूर्ण थी, जो कर्तव्य से कथित जानबूझकर लंबी अनुपस्थिति के कारण पारित की गई थी - इसके अलावा; समाप्ति को बरकरार रखने वाली अपीलों में पारित आदेश अस्पष्ट और गुप्त थे - सभी आदेश रद्द कर दिए गए - याचिकाकर्ता को सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया गया।

ये निर्धारित किया गया कि एक बार जब याचिकाकर्ता नियमित आधार पर सैन्य विज्ञान में प्रोफ़ेसर के रूप में प्रतिवादी-कॉलेज में सेवा कर रहा था, तो प्रतिवादी-कॉलेज के प्रबंधन के पास नियमित विभागीय जांच किये बिना दिनांक 5-9-1989 (अनुलग्नक पी- 6) के विवादित समाप्ति आदेश को पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा। ऐसा इसलिए कहा गया है, क्योंकि समाप्ति आदेश स्वभाव में कलंकात्मक है, जो कथित तौर पर जानबूझकर कर्तव्य से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण पारित किया गया है। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय

को यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी-कॉलेज का प्रबंधन विवादास्पद समाप्ति आदेश पारित करते समय अत्यंत मनमाने दृष्टिकोण पर आगे बढ़ा और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

(पैरा 7)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि हरियाणा संबद्ध कॉलेजों (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 7(1) और 7(2) में निहित कानून के अनिवार्य प्रावधान भी याचिकाकर्ता के बचाव में आया है।

(पैरा 8)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि विवादित समाप्ति आदेश पारित करने से पहले, प्रतिवादी-प्रबंधन द्वारा प्रतिवादी नंबर 2 से कोई अनुमोदन नहीं मांगा गया था। राज्य के विद्वान वकील द्वारा भी यही तर्क दिया गया है। जब याचिकाकर्ता ने वास्तव में आक्षेपित समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी-6) के खिलाफ आक्रोश जताया, तो उसने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अनुलग्नक पी-7 के माध्यम से अपनी अपील दायर की। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 ने खुद को गलत तरीके से निर्देशित किया, जब उन्होंने 27-2-1990 (अनुलग्नक पी-8) को पूरी तरह से गुप्त और नॉन-स्पीकिंग आदेश पारित करते हुए याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करा। प्रतिवादी नंबर 2 से कम से कम यह उम्मीद की जा रही थी

कि उसके पास जो भी कारण उपलब्ध था, वह उसे बताता, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा।

(पैरा 9)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि, प्रतिवादी नंबर 1 ने भी याचिकाकर्ता की अपील को दिनांक 27-5-1994 (अनुलग्नक पी -11) के पूरी तरह से गुप्त और नॉन-स्पीकिंग आदेश द्वारा फिर से खारिज कर दिया। चूंकि उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा पारित किए गए आदेशें के याचिकाकर्ता पर सिविल परिणाम थे, इसलिए वे तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करने के कानूनी दायित्व के तहत थे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 और साथ ही प्रतिवादी नंबर 2 कानून के अनुसार उचित आदेश पारित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं, जिसके कारण विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-8 और पी-11) भी कायम नहीं रखे जा सकते।

(पैरा 10)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि, राज्य के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क कि विवादित समाप्ति आदेश परिवीक्षा अवधि के दौरान पारित किया गया था और इसलिए, कोई विभागीय जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी, को खारिज कर दिया जाना चाहिए। यदि यह समाप्ति का एक सरल आदेश होता, तो राज्य के विद्वान वकील का ऐसा कहना उचित हो सकता था, लेकिन

वर्तमान मामले में, विवादित समाप्ति आदेश स्पष्ट रूप से एक कलंकपूर्ण आदेश था और इसे नियमित विभागीय कार्यवाही के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। अत: विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

(पैरा 12)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि, कि ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि आक्षेपित समाप्ति आदेश दिनांक 5-9-1989 (अनुलग्नक पी-6) को स्पष्ट रूप से अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना पाया गया है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27-2-1990 (अनुलग्नक पी) और साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-5-1994 (अनुलग्नक पी-11) पूरी तरह से गुप्त और नॉन-स्पीकिंग आदेश हैं जिन्हे कायम नहीं रखा जा सकता, इसलिए तीनों विवादित आदेशों को खारिज किया जाता है।

(पैरा 16)

इसके अलावा, यह निर्धारित किया गया कि, परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता को सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 17)

संदीप सिंगल,याचिकाकर्ता के वकील ।

ए.एस.चौधरी, अतिरिक्त ए.जी., हरियाणा।

आर.के.मलिक, वरिष्ठ अधिवक्ता सम्राट मलिक, प्रतिवादी संख्या 3 और 4 के वकील।

<u>रामेश्वर सिंह मलिक, न्यायाधीश (मौखिक):</u>

(1) वर्तमान रिट याचिका समाप्ति आदेश दिनांक 5.9.1989 (अनुलग्नक पी-6) अपीलीय आदेश दिनांक 27.2.1990 (अनुलग्नक पी-8) और आदेश दिनांक 27.5.1994 (अनुलग्नक पी-11) के विरुद्ध निर्देशित है, जिसके तहत प्रतिवादी-कॉलेज के प्रबंधन ने नियमित विभागीय जांच किए बिना, याचिकाकर्ता की सैन्य विज्ञान के नियमित प्रोफ़ेसर के तौर पर सेवाओं को समाप्त कर दिया।

(2) नोटिस ऑफ मोशन जारी किया गया और उसके अनुसरण में, केवल उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 की ओर से लिखित बयान दायर किया गया था।

(3) याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का कहना है कि पहले याचिकाकर्ता 19.8.1988 से 7.7.1989 तक तदर्थ आधार पर सैन्य विज्ञान में प्रोफ़ेसर के रूप में कार्यरत था। इसके बाद, याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश दिनांक 8.7.1989 (अनुलग्नक पी-2) द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया गया। उन्होंने आगे कहा कि नियुक्ति आदेश (अनुलग्नक पी-2) के अनुसार, याचिकाकर्ता को प्रतिवादी-कॉलेज द्वारा 31.7.1989 को शामिल होने की अनुमति दी गई थी और उसने

8.8.1989 तक काम किया। इसके बाद, याचिकाकर्ता बीमार पड़ गया और उसने चिकित्सा अवकाश के लिए उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 को आवेदन के साथ एक चिकित्सा प्रमाण पत्र भेजा। मेडिकल फिटनेस प्रमाणपत्र अनुलग्नक पी-4 है और उसके आधार पर, याचिकाकर्ता ने 4.9.1989 को ड्यूटी के लिए रिपोर्ट किया लेकिन उसे शामिल होने की अनुमति नहीं दी गई। अगले ही दिन, यानी 5.9.1989 को, याचिकाकर्ता ने निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा-प्रतिवादी संख्या 2 को अनुबंध पी-5 के माध्यम से आवेदन दिया, लेकिन जानबूझकर लंबे समय तक ड्यूटी से अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिवादी-कॉलेज के प्रबंधन ने 5.9.1989 को समाप्ति का आदेश बिना किसी विभागीय जांच के पारित कर दिया (अनुलग्नक पी-6) । व्यथित महसूस करते हुए, याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अपनी अपील (अनुलग्नक पी-7) दायर की, जिसने दिनांक 27.2.1990 (अनुलग्नक पी-8) के आदेश के तहत इसे खारिज कर दिया। याचिकाकर्ता ने अपनी अपील (अनुलग्नक पी-9) के माध्यम से राज्य सरकार से संपर्क किया, लेकिन राज्य सरकार ने दिनांक 27.5.1994 (अनुलग्नक पी-11) के आदेश के तहत इसे भी खारिज कर दिया। उनका यह भी कहना है कि जहां तक 1990 के सिविल सूट नंबर 589 का संबंध है, यह केवल प्रतिवादी-प्रबंधन के साथ काम करने की अवधि के लिए वेतन की सीमा की घोषणा के लिए एक मुकदमा था। याचिकाकर्ता ने सिविल कोर्ट के समक्ष आक्षेपित समाप्ति आदेश को इस कारण से चुनौती नहीं दी क्योंकि प्रतिवादी नंबर 2 के समक्ष उसकी अपील पर निर्णय लंबित था। उन्होंने

यह प्रस्तुत करते हुए निष्कर्ष निकाला कि चूंकि विवादित समाप्ति आदेश नियमित विभागीय जांच किए बिना पारित किया गया है और अपीलीय आदेश निरर्थक थे, इसलिए उन्हें रद्द किया जाना चाहिए। वह विवादित आदेशों को रद्द करके तत्काल रिट याचिका की स्वीकार करने का अनुरोध करते है।

(4) इसके विपरीत, उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील का कहना है कि यह याचिकाकर्ता का जानबूझकर अनुपस्थित होने का मामला था, उन्हें प्रतिवादी-कॉलेज के साथ सेवा करने में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी। याचिकाकर्ता को ड्यूटी में शामिल होने के लिए पर्याप्त अवसर दिए गए थे लेकिन वह उन कारणों से उपस्थित नहीं हुआ जो उसे खुद ज्ञात हैं। उन्होंने आगे कहा कि रिट याचिका भी देरी और खामियों से ग्रस्त थी, जो कि विवादित समाप्ति आदेश पारित होने के लगभग छह साल बाद दायर की गई थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि सिविल कोर्ट का दिनांक 30.8.1993 (अनुलग्नक पी-12) का फैसला याचिकाकर्ता के खिलाफ प्राड् न्याय होगा और वर्तमान रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी। उनका यह भी कहना है कि चूंकि याचिकाकर्ता ने गांव काहनौर, जिला रोहतक में एक निजी स्कूल खोला है, इसलिए याचिकाकर्ता के पास अपनी ड्यूटी में शामिल न होने का विशेष कारण था। उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने की प्रार्थना की।

(5) इसी तरह, राज्य के विद्वान वकील का कहना है कि गलती केवल याचिकाकर्ता की है। उन्होंने कभी भी प्रतिवादी-कॉलेज के साथ सेवा प्रदान करने में रुचि नहीं

दिखाई। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि समाप्ति आदेश परिवीक्षा अवधि के दौरान पारित किया गया था, इसलिए कोई नियमित विभागीय जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। उन्होंने आगे तर्क दिया कि चूंकि प्रतिवादी-प्रबंधन ने निदेशक, उच्च शिक्षा, हरियाणा-प्रतिवादी नंबर 2 से कोई मंजूरी नहीं मांगी थी, इसलिए राज्य के अधिकारी इस संबंध में दोषी नहीं थे। उन्होंने रिट याचिका को खारिज करने का भी अनुरोध किया।

(6) पक्षों के विद्वान वकीलों को काफी विस्तार से सुनने के बाद, मामले के रिकॉर्ड का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने और उठाए गए प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचारशील विचार करने के बाद, यह न्यायालय इस बात पर सहमत है कि वर्तमान की दी गई तथ्यात्मक स्थिति में मामले में, तत्काल रिट याचिका स्वीकार की जानी चाहिए। ऐसा कहने कारण एक से अधिक हैं, जिन्हें आगे दर्ज किया जा रहा है।

(7) यह रिकॉर्ड पर निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता को नियुक्ति आदेश दिनांक 8.7.1989 (अनुलग्नक पी-2) द्वारा नियमित आधार पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता द्वारा रिट याचिका के पैरा 5 में लिया गया विशिष्ट कथन कि उसे 31.7.1989 को प्रोफ़ेसर के रूप में शामिल होने की अनुमति दी गई थी, रिकॉर्ड में निर्विवाद रूप से दर्ज किया गया है। जब एक बार याचिकाकर्ता नियमित आधार पर प्रतिवादी-कॉलेज में सैन्य विज्ञान में प्रोफ़ेसर के रूप में सेवा कर रहा था, तो प्रतिवादी-कॉलेज के प्रबंधन के पास नियमित विभागीय जांच संचालन के बिना,

दिनांक 5.9.1989 (अनुलग्नक पी -6) के आक्षेपित समाप्ति आदेश को पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। ऐसा इसलिए कहा गया है, क्योंकि समाप्ति आदेश में कलंकात्मक है, तथा याचिकाकर्ता के जानबूझकर कर्तव्य से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण पारित किया गया है। ऐसा कहने के बाद, इस न्यायालय को यह निष्कर्ष निकालने में कोई झिझक नहीं है कि प्रतिवादी-कॉलेज का प्रबंधन विवादास्पद समाप्ति आदेश पारित करते समय मनमाने दृष्टिकोण पर आगे बढ़ा और इसे बरकरार नहीं रखा जा सकता।

(8) हरियाणा संबद्ध कॉलेज (सेवा की सुरक्षा) अधिनियम, 1979 (संक्षेप में 'अधिनियम') की धारा 7(1) और (2) में निहित कानून के अनिवार्य प्रावधान भी याचिकाकर्ता के बचाव में आते हैं। अधिनियम की धारा 7 का प्रासंगिक भाग इस प्रकार है:-

> *“7(1) किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, हटाया नहीं जाएगा या रैंक में कटौती नहीं की जाएगी जांच के बिना जिसमें उसे उसके खिलाफ आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया हो;*

(2) बर्खास्तगी या सेवा से हटाने या रैंक में कमी का जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि इसे निदेशक द्वारा अनुमोदित नहीं किया जाता है।

(9) यह स्वीकृत है कि, विवादित समाप्ति आदेश पारित करने से पहले, प्रतिवादी-प्रबंधन द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 से कोई अनुमोदन नहीं मांगा गया था। राज्य के विद्वान वकील द्वारा भी यही तर्क दिया गया है। जब याचिकाकर्ता वास्तव में आक्षेपित समाप्ति आदेश (अनुलग्नक पी-6) से व्यथित था, तो उसने प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष अनुबंध पी-7 के माध्यम से अपनी अपील दायर की। हालाँकि, प्रतिवादी संख्या 2 ने याचिकाकर्ता की अपील को खारिज करते हुए दिनांक 27.2.1990 (अनुलग्नक पी-8) को पूरी तरह से नॉन-स्पीकिंग और गुप्त आदेश पारित करते हुए खुद को गलत दिशा में निर्देशित किया। प्रतिवादी नंबर 2 से कम से कम यह उम्मीद की जा रही थी कि उसके पास जो भी कारण उपलब्ध था, वह उसे बताता, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा।

(10) इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 ने भी याचिकाकर्ता की अपील को दिनांक 27.5.1994 (अनुलग्नक पी-11) को पूरी तरह से नॉन-स्पीकिंग और गुप्त आदेश द्वारा फिर से खारिज कर दिया। चूंकि उत्तरदाताओं संख्या 1 और 2 द्वारा पारित किए गए आदेशें के याचिकाकर्ता पर सिविल परिणाम थे, इसलिए वे तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित करने के कानूनी दायित्व के तहत थे। हालाँकि, वर्तमान मामले में, प्रतिवादी नंबर 1 और साथ ही प्रतिवादी नंबर 2 कानून के अनुसार

उचित आदेश पारित करने के अपने कर्तव्य में विफल रहे हैं, जिसके कारण विवादित आदेश (अनुलग्नक पी-8 और पी-11) भी कायम नहीं रखे जा सकते।

(11) कथित देरी और चूक के संबंध में उत्तरदाताओं संख्या 3 और 4 के विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा उठाए गए तर्क पर आते हुए, इस पर विधिवत विचार किया गया है लेकिन इन्हे बिना किसी तथ्य के पाया गया है। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि याचिकाकर्ता, उत्तरदाताओं नंबर 1 और 2 के समक्ष अपना पक्ष रख रहा था। अंततः प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा 27.5.1994 (अनुलग्नक पी-11) को आदेश पारित किया गया और याचिकाकर्ता ने मार्च 1995 के महीने में इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, जिसके कारण, तत्काल रिट याचिका को देरी और अति विलंब से पीड़ित नहीं कहा जा सकता है।

(12) इसी तरह, राज्य के विद्वान वकील द्वारा उठाए गए तर्क को खारिज कर दिया जाना चाहिए कि आक्षेपित समाप्ति आदेश परिवीक्षा अवधि के दौरान पारित किया गया था और इसलिए, कोई विभागीय जांच आयोजित करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि यह समाप्ति का एक सरल आदेश होता, तो राज्य के विद्वान वकील का ऐसा कहना उचित हो सकता था, लेकिन वर्तमान मामले में, विवादित समाप्ति आदेश स्पष्ट रूप से एक कलंकपूर्ण आदेश था और इसे नियमित विभागीय कार्यवाही के बिना पारित नहीं किया जा सकता था। अत: विवादित आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।

(13) इस न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कई निर्णयों से भी समर्थन मिलता है। प्रशासनिक कार्यों के लिए ऑडी अल्टरम पार्टेम के नियम की प्रयोज्यता से संबंधित कानून के विकास का पता **ए.के क्रेपक बनाम भारत संघ[1], रिज बनाम बाल्डविन[2], सईदुर रहमान बनाम बिहार राज्य[3], उड़ीसा राज्य बनाम डॉ. (मिस) बीनापानी देई[4], मेनका गांधी बनाम भारत संघ[5]** और **मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त[6]** से लगाया जा सकता है।

(14) इन सभी निर्णयों में निर्धारित कानून का माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगातार निर्णयों में पालन किया गया है और हाल ही में **श्री राधा श्याम (मृत) एल.आर. और अन्य बनाम यूपी राज्य और अन्य[7], दर्शन लाल नागपाल (मृत)एल.आर. बनाम दिल्ली की एनसीटी सरकार और अन्य[8]**, के फैसला में।

(15) कोई अन्य तर्क नहीं उठाया गया।

(16) ऊपर उल्लिखित मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, उपरोक्त कारणों के साथ, इस न्यायालय का विचार है कि चूंकि आक्षेपित समाप्ति आदेश दिनांक 5-9-1989 (अनुलग्नक पी-6) को स्पष्ट रूप से

---

[1] (1962) 2 एससीसी 262
[2] 1964 ए.सी. 40
[3] (1973) 3 एससीसी 333
[4] एआईआर 1976 एससी 1269
[5] (1978) 1 एससीसी 248
[6] (1978)1 एससीसी 405
[7] (2011) 5 एससीसी 553
[8] (2012) 2 एससीसी 327

अवैध और अधिकार क्षेत्र के बिना पाया गया है, इसे कायम नहीं रखा जा सकता है। इसी प्रकार, प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27-2-1990 (अनुलग्नक पी) और साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-5-1994 (अनुलग्नक पी-11) पूरी तरह से गुप्त और नॉन-स्पीकिंग आदेश हैं जिन्हे कायम नहीं रखा जा सकता, इसलिए तीनों विवादित आदेशों को खारिज किया जाता है।

(17) नतीजतन, याचिकाकर्ता को सभी परिणामी सेवा लाभों के साथ सेवा में बहाल करने का निर्देश दिया जाता है। प्रतिवादी अधिकारियों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने दें।

(18) परिणामस्वरूप, उपरोक्त टिप्पणियों और जारी किए गए निर्देशों के साथ, तत्काल रिट याचिका स्वीकार की जाती है, हालांकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और

आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

आदित्य जैन

सिविल जज (जूनियर डिविजन) व प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

पानीपत, हरियाणा|